



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 1967 (पौष 9, 1889)
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 1967 (PAUSA 9, 1889)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 3 नवम्बर 1967 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 3rd November 1967 :—

सं० Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subjects
------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------

Nil

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से इस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes

विषय सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)		पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	911	भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1351	भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	979
		भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	—
		भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रश्न समितियों की रिपोर्ट .	—

भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2107
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	4837
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	297
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1033

भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	555
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	187
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	865
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	207
पूरक सं० 50—	
9 दिसम्बर 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	2089
18 नवम्बर 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	2099

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	911
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1351
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	979
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2107

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	4837
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	297
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1033
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	555
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	187
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	865
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	207
SUPPLEMENT No. 50—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 9th December 1967	2089
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 18th November 1967	2099

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 1967

सं० 19(15) प्लॉट (बी०)/67—भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 27 सितम्बर 1967 में प्रकाशित वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प संख्या 19(15) प्लॉट (बी०)/67 दिनांक 26 सितम्बर 1967 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे; अर्थात् :—

पैराग्राफ 4 के अन्तर्गत मद संख्या (5) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“(6) डा० के० टी० जैकब,
गवेषणा निदेशक-सह-रबड़ उत्पादन आयुक्त,
रबड़ बोर्ड,
कोट्टायम (केरल) सदस्य सचिव”

आदेश

आदेश दिया जाता है कि शुद्धि-पत्र सभी सम्बद्धों को भेजा जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि शुद्धि-पत्र को सार्वजनिक जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

पी० सी० अलक्साडर, संयुक्त सचिव

औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 1967

सं० 48/67-आई० एल० पी० आई० सी०—राष्ट्रपति, श्री के० के० सुब्रह्मण्यन, को, औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में स्थापित औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली संबंधी विशेषज्ञ समिति में 4 दिसम्बर 1967 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक उप-निदेशक नियुक्त करते हैं।

एन० शिवारमन, अवर सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 1967

सं० 3-33/67-मशीनरी—राष्ट्रपति जी श्री करतार सिंह यादव को 7 नवम्बर 1967 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र, हिसार (हरियाणा) में निदेशक के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

एन० रंगानाथन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1967

संकल्प

सं० 2-65/66-सी० सी० 1—भारत सरकार ने भारतीय नारियल विकास परिषद् को, जो संकल्प संख्या 6-9/65-रिआर्ग० (सी० सी०) दिनांक 16 अप्रैल 1966 को गठित की गई थी, तत्काल से पुनर्गठित करने का निश्चय किया है। पुनर्गठित विकास परिषद् का गठन निम्न प्रकार होगा :—

1. अध्यक्ष : उत्पादकों का एक प्रतिनिधि जिसको भारत सरकार नियुक्त करे।
2. उपाध्यक्ष : सचिव, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)।
3. सदस्य:

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

(क) राज्य सरकारें : निम्नलिखित राज्य सरकारें अपनी सरकार के कृषि विभाग का एक-एक प्रतिनिधि नामजद करेंगी :—

- (1) केरल
- (2) मद्रास

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1967

सं० 1-2/65-एम० ई० आई०—भूतपूर्व इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय के संकल्प संख्या 1-2/63-एम० ई० आई० दिनांक 25 मार्च 1964 के संदर्भ में जो बाल बियरिंग उद्योग के लिए एक नामिका गठित करने के सम्बन्ध में था।

2. यह निश्चय किया गया है कि श्री पी० टी० ग्रुफमैन के स्थान पर, जो अब भारत से बाहर चले गये हैं, श्री सी० ओ० ब्लोमबर्ग, प्रबन्ध निदेशक, एसोसियेटेड बियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई बाल बियरिंग उद्योग की नामिका के सदस्य होंगे।

3. यह भी आगे निश्चय किया गया है कि श्री एल० के० धवन के स्थान पर, जो अब इलाहाबाद में प्रभागीय अधीक्षक, उत्तर रेलवे के पद पर स्थानान्तरित हो गये हैं, श्री अमरजीत सिंह, संयुक्त निदेशक, रेलवे स्टोर्स (डेव०), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली बाल बियरिंग उद्योग की नामिका के सदस्य होंगे।

आई० वी० भुनकत, अवर सचिव

- (3) मैसूर
- (4) आन्ध्र प्रदेश
- (5) उड़ीसा

(ख) केन्द्रीय सरकार .

- (1) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।
- (2) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
- (3) कृषि आयुक्त, भारत सरकार ।
- (4) महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ।

(ग) उत्पादकों के प्रतिनिधि : प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों के निम्नलिखित 10 प्रतिनिधि जिनको राज्य सरकारें नाम-जद करेंगी :—

केरल	3
मद्रास	2
मैसूर	1
आन्ध्र प्रदेश	1
महाराष्ट्र	1
पश्चिम बंगाल	1
उड़ीसा	1

(घ) व्यापारियों के प्रतिनिधि : व्यापारियों के तीन प्रतिनिधि जिनकी नामजदगी परिषद् के लिए की जाएगी । ये प्रतिनिधि उन उम्मीदवारों में छांटे जायेंगे जिनके नाम विभिन्न स्वीकृत चैम्बर आफ कामर्स तथा अन्य व्यापार संस्थाओं द्वारा सुझाये जायेंगे ।

(ङ) उद्योग के प्रतिनिधि : उद्योग के तीन प्रतिनिधि ।

(च) अन्य : संसद् के तीन सदस्य जिनकी नामजदगी भारत सरकार, संसदीय मामलों के विभाग की सलाह से निम्न रूप से करेंगी :—

- I. 1. श्री डी० पी० करमाकर, सदस्य, राज्य सभा ।
2. श्री द्वापायन सेन, सदस्य, लोक सभा ।
3. श्री के० एम० अब्राहम, सदस्य, लोक सभा ।

II. श्री सी० आर० बसप्पा, गांधी नगर, तुमकुर (मैसूर) ।

(छ) समय समय पर सरकार द्वारा नामजद किये गये ऐसे अनिर्वृत व्यक्ति, जो कि परिषद् में उन हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनके लिए कोई भी प्रतिनिधि पहले से नहीं है ।

4. **सदस्य सचिव** : निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय नारियल विकास, एरनाकुलम, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) ।

5. **प्रेक्षक** : (यह लोग परिषद् के सदस्य तो नहीं होंगे, परन्तु परिषद् के कार्यों में सहायता देने के लिए निरपवाद रूप से आमन्त्रित किये जायेंगे) ।

- (1) अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम या उसका प्रतिनिधि ।
- (2) कृषि विपणन सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), नागपुर ।
- (3) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय से सम्बन्धित संयुक्त सचिव (वित्त) ।
- (4) अर्थ तथा अंक सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) ।

(5) रेलवे मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(6) निदेशक, केन्द्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र, कायगुलम (केरल) ।

(7) निदेशक, केन्द्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र, कसारागाड (केरल) ।

(8) निदेशक, केन्द्रीय, खाद्य, औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर ।

(9) सचिव, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली ।

(10) उप-आयुक्त (होर्ट) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) ।

(11) उप-आयुक्त (निर्यात वृद्धि), खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) ।

2. यह परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी तथा इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नारियल विकास कार्यक्रम पर समय समय पर विचार करना ।

(2) नारियल उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि में रखकर नारियल विकास कार्य की प्रगति पर विचार करना और पुनर्विलोकन करना ।

(3) नारियल विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की, जहाँ भी आवश्यक हो, प्रगति को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(4) नारियल विपणन तथा व्यापार की समस्याओं पर जिसमें मूल्य नीति भी सम्मिलित है, विचार तथा पुनर्विलोकन करना तथा इनमें सुधार के लिए सुझाव देना ।

(5) समय समय पर भारत सरकार द्वारा परिषद् को सौंपा गया अन्य कार्य ।

3. उत्पादन क्षेत्रों में स्थित व्यापार तथा उद्योग के प्रमुख केन्द्रों में परिषद् समय समय पर अपनी बैठक किया करेगी तथा भारत सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिश किया करेगी ।

4. परिषद् के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी । परन्तु इस परिषद् के लिए संसद् के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष या उस समय तक जब तक कि वे संसद् के सदस्य रहते हैं, जी भी कम हो, सीमित रहेगी । भारत सरकार इस अवधि को बढ़ा सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, समस्त संघ क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों, योजना आयोग, मन्त्रीमण्डल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाये ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारतीय राज-पत्र में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाये ।

सं० 9(13)/67-सी० सी० 1—भारत सरकार ने भारतीय लाख विकास परिषद् को, जो संकल्प संख्या 6-10-1965—रिआर्ग० (सी० सी०) दिनांक 14 जन 1966 को गठित की गई

पी, तत्काल से पुनर्गठित करने का निश्चय किया है। पुनर्गठित विकास परिषद् का गठन निम्न प्रकार होगा —

1. अध्यक्ष, निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, लाख विकास, रांची।
2. उपाध्यक्ष : उत्पादकों का एक प्रतिनिधि जिनको भारत सरकार नामजद करेगी।
3. सदस्य :

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

(क) राज्य सरकारें—निम्नलिखित राज्य सरकारें अपनी सरकार के कृषि विभाग का एक-एक प्रतिनिधि नामजद करेंगी। —

- (1) बिहार
- (2) मध्य प्रदेश
- (3) पश्चिम बंगाल
- (4) महाराष्ट्र
- (5) उड़ीसा

(ख) केन्द्रीय सरकार :

- (1) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि।
- (2) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
- (3) कृषि आयुक्त, भारत सरकार।
- (4) अध्यक्ष, लाख नियत विकास परिषद्।
- (5) महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या उसका प्रतिनिधि।

(ग) उत्पादकों के प्रतिनिधि : प्रमुख लाख उत्पादक राज्यों के छः उत्पादक जैसे दो बिहार से और एक-एक मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से, जिनको राज्य सरकारें नामजद करेंगी।

(घ) व्यापारियों के प्रतिनिधि : व्यापारियों के तीन प्रतिनिधि जिनकी नामजदगी परिषद् के लिए की जाएगी। ये प्रतिनिधि उन उम्मीदवारों में छाटे जायेंगे जिनके नाम विभिन्न स्वीकृत चैम्बर आफ कामर्स तथा अन्य व्यापार संस्थाओं द्वारा सुझाये जायेंगे।

(ङ) उद्योग के प्रतिनिधि : उद्योग के तीन प्रतिनिधि।

(च) अन्य : (1) संसद् के तीन सदस्य, जिनकी नामजदगी भारत सरकार, संसदीय मामलों के विभाग की सलाह से निम्न प्रकार से करेगी :—

- (अ) श्री बाबूनाथ सिंह, सदस्य, लोक सभा।
- (ब) श्री ईश्वर मरांडी, सदस्य, लोक सभा।
- (स) श्री भूपानी चरण पटनायक, सदस्य, राज्य सभा।

(2) निदेशक, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, नामकुम, रांची (बिहार)।

(छ) समय समय पर सरकार द्वारा नामजद किये गये ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जो कि परिषद् में उन हितों का प्रतिनिधित्व करेगे जिनके लिए कोई भी प्रतिनिधि पहले से नहीं है।

4. सदस्य सचिव : उप-निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, लाख विकास, रांची, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग)।

5. प्रश्नक : (यह लोग परिषद् के सदस्य तो नहीं होंगे, परन्तु परिषद् के कार्यों में सहायता देने के लिये निरपवाद रूप से आमन्त्रित किये जायेंगे।)

- (1) अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम या उसका प्रतिनिधि।
- (2) कृषि विपणन सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग), नागपुर।
- (3) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय से सम्बन्धित संयुक्त सचिव (वित्त)।
- (4) अर्थ तथा अंक सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग)।
- (5) रेलवे मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि।
- (6) बिहार स्टेट लाख कोआपरेटिव मार्किटिंग फ़ैडरेशन लिमिटेड, रांची।
- (7) उप आयुक्त, (ई० पी०), खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग)।
- (8) सचिव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या उसका प्रतिनिधि।

2. यह परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी तथा इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :—

- (1) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये लाख विकास कार्यक्रम पर समय समय पर विचार करना।
- (2) लाख उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि में रखकर लाख विकास कार्यों की प्रगति पर विचार करना और पुनर्विलोकन करना।
- (3) लाख विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की, जहाँ भी आवश्यक हो, प्रगति को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- (4) लाख विपणन तथा व्यापार की समस्याओं पर जिसमें मूल्य नीति भी सम्मिलित है, विचार तथा पुनर्विलोकन करना तथा इनमें सुधार के लिए सुझाव देना।
- (5) समय समय पर भारत सरकार द्वारा परिषद् को सौंपा गया अन्य कार्य।

3. उत्पादन क्षेत्रों में स्थित व्यापार तथा उद्योग के प्रमुख केन्द्रों में परिषद् समय समय पर अपनी बैठक किया करेगी तथा भारत सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिश किया करेगी।

4. परिषद् के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी। परन्तु इस परिषद् के लिए संसद् के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष या उस समय तक जब तक कि वे संसद् के सदस्य रहते हैं, जो भी कम हो, सीमित रहेंगे। भारत सरकार इस अवधि को बढ़ा सकती है।

आवेश

आवेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, समस्त मंत्रालयों के प्रशासकों और भारत सरकार के मन्त्र मन्त्रालयों, योजना आयोग, मन्त्रीमण्डल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारतीय राज-पत्र में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाये।

एस० जे० मजूमदार, अतिरिक्त सचिव

भारतीय कृषिअनुसंधान परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 1967

सं० 29(1)/66-समन्वय (1)—पूना विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति डा० डी० आर० गाडगिल ने, जो कि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कृषि-शिक्षा की स्थायी समिति के लिए 30 जुलाई 1969 को समाप्त होने वाली अवधि तक अथवा जब तक उनका उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं हो जाता—इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो, सदस्य मनोनीत किए गए थे, परिषद् की कृषि समिति में सदस्य बने रहने से अपनी असमर्थता प्रगट की है। इस प्रकार सोसाइटी की नियमावली के नियम 77, जिसके साथ नियम 11 भी पढ़ा जाए, में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार डा० गाडगिल अब समिति के सदस्य नहीं रहे हैं।

अतः डा० डी० आर० गाडगिल के स्थान पर एतद् द्वारा प्रोफेसर वी० एम० डान्डेकर, डायरेक्टर, गोखले इन्स्टीट्यूट आफ पालीटेक्स एण्ड इकानामिक्स, पूना, को विश्वविद्यालय आयोग के प्रतिनिधि के रूप में 30 जुलाई 1969 की अवधि तक अथवा जब तक उक्त समिति में उनका उत्तराधिकारी मनोनीत न किया जाए—इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो, कृषि-शिक्षा की स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 20 दिसम्बर 1967

सं० 30(1)/67-सी० डी० एन०(1)—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 34 के उपबन्धों के अन्तर्गत, जिसके साथ नियम 35 तथा 10 भी पढ़े जायें, निम्नलिखित व्यक्ति जो कि 25 अक्टूबर 1967 से परिषद् की शासी निकाय, जिसका पुनर्गठन इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 2-7/66-रिआर्ग (सी० सी०) दिनांक 17 फरवरी 1966 के अन्तर्गत किया गया था, के सदस्य नहीं रहे थे, उन्हें नियम 35 के अन्तर्गत, जिसके साथ नियम 11(बी०) भी पढ़ा जाय, एतद् द्वारा अर्वाशष्ट काल, अर्थात् 25 अक्टूबर 1967 से 16 फरवरी 1969 तक अथवा जब तक उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति न हो जाय, दोनों में से जो भी अवधि पहले समाप्त हो, के लिए शासी निकाय का सदस्य पुनः नियुक्त किया जाता है :—

1. डा० विक्रम ए० साराभाई,
अध्यक्ष,
अणुशक्ति आयोग, बम्बई।
2. डा० एम० डी० पटेल,
निदेशक,
कृषि संस्थान, अनन्त।

सं० 30(1)/67-सी० डी० एन०(1)—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 35 के उपबन्धों के अन्तर्गत, जिसको नियम 11 (बी०) के साथ पढ़ा जाय, निम्नलिखित व्यक्ति जिन्हें परिषद् की शासी निकाय का, जिसका पुनर्गठन इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 2-7/66-रिआर्ग (सी० सी०) दिनांक 17 फरवरी 1966 के अन्तर्गत किया गया था, सदस्य नियुक्त किया गया था, उस समिति के दिनांक 25 अक्टूबर 1967 से सदस्य नहीं रहे :—

1. श्री एन० नरोत्तम रेड्डी,
सदस्य, राज्य सभा,
हैदराबाद।
2. श्री एम० वाई० घोरपाड़े,
शिवपुर,
जिला बेल्लारी (मैसूर)।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 34 के उपबन्धों के अन्तर्गत, जिसको नियम 35 तथा 10 के साथ पढ़ा जाय, निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद् द्वारा 15 दिसम्बर 1967 से 16 फरवरी 1969 तक अथवा जब तक उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति न हो जाय, दोनों में से जो भी अवधि पहले समाप्त हो, के लिए परिषद् की शासी निकाय का सदस्य नियुक्त किया जाता है :

1. श्री शिशिर कुमार,
सदस्य राज्य सभा,
अर्राह, बिहार।
2. श्री शाहनवाज खां,
“ऐथल फार्म”, ग्राम ऐथेल,
जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

पी० एस० हरिहरन, उप-सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 1967

सं० 22/10/67-सी० ए० आई०(2)—शिक्षा मंत्रालय की तारीख 4 अगस्त 1966 की अधिसूचना संख्या 14/3/65-सी०-5 के संशोधन में थिरु पी० के० नाम्बियार, आई० ए० एस०, क्यूरेटर, मद्रास रिकार्ड आफिस, मद्रास को श्री जे० के० मनिकम, भूतपूर्व क्यूरेटर, मद्रास रिकार्ड आफिस, मद्रास के स्थान पर 3 अप्रैल, 1971 के समाप्त होने वाली अवधि के शेष भाग के लिए भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का साधारण सदस्य नियुक्त किया जाता है।

ए० एस० तलवार, अवर सचिव

SUPREME COURT OF INDIA*New Delhi, the 20th November 1967*

No. F. 22/68-SCA(Genl.) : In pursuance of sub-clause (3) of rule 4 of Order II, of Supreme Court Rules, 1966, it is hereby notified that the following days will be observed as Court holidays during the year 1968.

Name of Holiday	Month & Date	Day of the Week	No. of days.
New Year's Day	1st January	Monday	1
Id-ul-Fitr	2nd January	Tuesday	1
Republic Day ..	26th January	Friday	1
Holi	14th and 15th March	Thursday & Friday	2
Muharram	9th April	Tuesday	1
Good Friday ..	12th April	Friday	1
Balsakhi	13th April	Saturday	1
Independence Day ..	15th August	Thursday	1
Janam Ashtmi ..	16th August	Friday	1
Dussehra & Mahatma Gandhi's Birthday	30th September to 5th October	Monday to Saturday	6
Diwali	21st & 22nd October	Monday & Tuesday	2
Guru Nanak's Birthday	5th November	Tuesday	1
Id-ul-Fitr	21st December	Saturday	1
Christmas & New Year Holidays	23rd December 1968 to 4th January 1969 (Both days inclusive)		13

Y. D. DESAI, Registrar

PLANNING COMMISSION**RESOLUTION***New Delhi, the 20th November 1967*

No. 15/2/67-Edn.—The Government have decided to dissolve with immediate effect the Working Group for Parent-teacher Participation which was set up under Planning Commission Resolution No. 1/23/64-Edn., dated the 18th September, 1965 to draw up an integrated programme of action by the Parent-Teacher Association of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

G. C. BAVEJA, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS**(Department of Industrial Development)***New Delhi, the 12th December 1967*

No. 1-2/65-MEI.—Reference the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering Resolution No. 1-2/63-MEI, dated the 25th March, 1964 constituting a Panel for the Ball Bearing Industry.

2. It has been decided that Mr. C. O. Blomberg, Managing Director, Associated Bearing Company Limited, Bombay shall be a Member of the Panel for Ball Bearing Industry vice Mr. P. T. Gruffmann, who has since left India.

3. It has been further decided that Shri Amarjit Singh, Joint Director, Railway Stores (Dev.), Railway Board, New Delhi shall be a Member of the Panel for Ball Bearing Industry vice Shri L. K. Dhawan, who has since been transferred to Allahabad as Divisional Superintendent, Northern Railways.

I. V. CHUNKATH, Under Secy.

(Industrial Licensing Policy Inquiry Committee)*New Delhi, the 18th December 1967*

No. 1(48)/67-ILPIC.—The President is pleased to appoint Shri K. K. Subrahmanian, as Deputy Director in the Export

Committee on Industrial Licensing System, set up in the Ministry of Industrial Development & Company Affairs, (Department of Industrial Development), with effect from the 4th December, 1967 (forenoon) and until further orders.

N. SIVARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS**(Department of Iron and Steel)****RESOLUTION***New Delhi, the 21st November 1967*

No. RM-2(23)/67.—In the Department of Iron & Steel Resolution No. RM-2(23)/67 dated October 21, 1967 a Committee on Joint Sampling of Coal consisting of 7 Members was set up. It has now been decided to include the name of the following also as a Member of this Committee :—

Shri R. Lall,
Messrs. Andrew Yule & Co. Ltd.,
8, Clive Row,
Calcutta-1.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

H. LAL, Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION**(Department of Agriculture)***New Delhi, the 25th November 1967*

No. 3-33/67-MY.—The President is pleased to appoint Shri Kartar Singh Yadav as Director, Tractor Training Centre Hissar (Haryana) in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 7th November, 1967, until further orders.

N. RANGANATHAN, Under Secy.

RESOLUTIONS*New Delhi, the 15th December 1967*

No. 2-65/66-C.C.I.—The Government of India have decided to reconstitute with immediate effect the Indian Coconut Development Council set up vide their Resolution No. F. 6-9/65-Reogn. (CC), dated the 16th April, 1966. The reconstituted Council will consist of the following :

I. CHAIRMAN

A growers representative to be nominated by the Government of India.

II. VICE-CHAIRMAN

Secretary to the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Agriculture).

III. MEMBERS*Representative of the Central and State Governments***(a) State**

One representative each of the State Government in the Department of Agriculture to be nominated by the Governments of:

- (i) Kerala.
- (ii) Madras.
- (iii) Mysore.
- (iv) Andhra Pradesh.
- (v) Orissa.

(b) Central Government

- (i) One representative of the Planning Commission.
- (ii) One representative of the Ministry of Commerce.
- (iii) Agricultural Commissioner to the Government of India.
- (iv) Director General, Indian Council of Agricultural Research or his representative.

(c) *Growers Representatives*

Ten growers' representatives from the major growing States i.e., 3 from Kerala, 2 from Madras and one each from Mysore, Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Orissa to be nominated by these Governments.

(d) *Representatives of Traders*

Three representative of traders to be nominated on the Council out of the candidates recommended by various recognised Chambers of Commerce and other Trade Bodies.

(e) *Representatives of Industry*

Three representatives of Industry.

(f) *Others*

(i) Three members of Parliament nominated by the Government of India in consultation with the Department of Parliamentary Affairs as mentioned below :

- (a) Shri D. P. Karmakar, Member, Rajya Sabha.
- (b) Shri Dwaipayen Sen, Member, Lok Sabha.
- (c) Shri K. M. Abraham, Member, Lok Sabha.

(ii) Shri C. R. Basappa, Gandhi Nagar, Tumkur (Mysore).

(g) Such additional persons as may, from time to time be nominated by the Government of India to represent interest(s) not already represented on the Council.

IV. *MEMBER-SECRETARY*

The Director, Regional Office, Coconut Development, Ernakulam, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

V. *OBSERVERS*

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

1. Chariman, State Trading Corporation or representative.
2. Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) Nagpur.
3. Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).
4. Economic and Statistical Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Agriculture).
5. A representative of Railways.
6. Director, Central Coconut Research Station, Kayangulam (Kerala).
7. Director, Central Coconut Research Station, Kasargod (Kerala).
8. Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
9. Secretary, National Cooperative Development Corporation.
10. Deputy Commissioner (Hort.) Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).
11. Deputy Commissioner (Export Promotion), Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

- (i) to consider, from time to time, the Coconut Development Programmes formulated by the Central and State Governments,
- (ii) to consider and review the progress of Coconut development in context of targets laid down;
- (iii) to recommend measures for accelerating the tempo of development programme/Schemes, wherever necessary;

(iv) to consider and review the problems of Coconut marketing and trade, including price policy, and to make suggestions for improvement; and

(v) any other function, which may from time to time, be assigned by the Government of India to the Council.

3. The Council will meet periodically at important centres of trade and industry, in areas in which coconut is grown and will make its recommendations to the Government of India.

4. The terms of the members of the Council will be for three years. Members of Parliament will cease to be members of the Council as soon as they cease to be members of Parliament or after 3 years whichever is earlier. The term may be extended by the Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariates.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. 9-13/67-C.C.I.—The Government of India have decided to reconstitute with immediate effect the Indian Lac Development Council set up vide their Resolution No. 6-10/65-Reorgn. (Admn.) dated the 14th June, 1966. The reconstituted Council will consist of the following :—

I. *CHAIRMAN*

Director, Regional Office, Lac Development, Ranchi.

II. *VICE-CHAIRMAN*

A growers' representative to be nominated by the Government of India.

III. *MEMBERS*(a) *Representatives of the State Governments*

One representative each of the State Government in the Department of Agriculture to be nominated by the Government of—

- (i) Bihar.
- (ii) Madhya Pradesh.
- (iii) West Bengal.
- (iv) Maharashtra.
- (v) Orissa.

(b) *Representatives of the Central Government*

- (i) One representative of the Planning Commission.
- (ii) One representative of the Ministry of Commerce.
- (iii) Agricultural Commissioner to the Government of India.
- (iv) Chairman, Shellac Export Promotion Council.
- (v) Director General, Indian Council of Agricultural Research or his representative.

(c) *Growers' representatives*

Six growers' representatives from the major Lac Growing States i.e., two from Bihar and one each from Madhya Pradesh, West Bengal, Orissa and Uttar Pradesh to be nominated by these Governments.

(d) *Representatives of the Trade*

Three representatives of Trade, to be nominated on the Council out of the candidates recommended by various recognised chambers of Commerce and other trade bodies.

(e) *Representatives of the Industry*

Three representatives of Industry.

(f) *Others*

(i) Three members of Parliament nominated by the Government of India in consultation with the Department of Parliamentary Affairs as mentioned below :—

- (a) Shri Babunath Singh, Member, Lok Sabha.
 (b) Shri Iswar Morandi, Member, Lok Sabha.
 (c) Shri Bhabhani Charan Pattanayak, Member, Rajya Sabha.
 (ii) Director, Indian Lac Research Institute, Namkum, Ranchi (Bihar).
 (g) *Such additional persons as may from time to time, be nominated by the Government of India to represent interest(s) not already represented in the Council.*

IV. MEMBER-SECRETARY

Deputy Director, Regional Office, Lac Development, Ranchi, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture)

V. OBSERVERS

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations)

- (1) Chairman, State Trading Corporation or representative.
 - (2) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Agriculture), Nagpur.
 - (3) Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Agriculture).
 - (4) Economics and Statistical Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Agriculture)
 - (5) A representative of Railways.
 - (6) Bihar State Lac Cooperative Marketing Federation Ltd., Ranchi.
 - (7) Deputy Commissioner (E.P.), Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).
 - (8) The Secretary, National Cooperative Development Corporation or his nominee.
2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—
- (i) to consider, from time to time, the Lac Development Programmes formulated by the Central and State Government;
 - (ii) to consider and review the progress of lac development in the context of targets laid down;
 - (iii) to recommend measures for accelerating the tempo of development programmes/schemes, wherever necessary;
 - (iv) to consider the review problems of lac marketing and trade, including price policy and of make suggestions for improvement; and
 - (v) any other function, which may from time to time, be assigned by the Government of India to the Council.

3. The Council will meet periodically at important centres of trade and industry, in areas in which lac is cultivated and will make its recommendations to the Government of India

4. The term of members of the Council will be for three years. Members of Parliament will cease to be members of the Council as soon as they cease to be members of Parliament or after 3 years whichever is earlier. The term may be extended by the Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 18th December 1967

No. 7-21/66-LDI/III.—The Government of India has decided that the Evaluation Committee to evaluate the working of the Central Council of Gosamvardhana since its inception which was set up vide this Ministry's Resolution No.

7-21/66-LDI/III dated 28th February, 1967 and extended upto 31-12-1967 vide this Ministry's resolution of even number dated 18th September, 1967 may submit its report to Government by the 31st March, 1968.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Central Council of Gosamvardhana.

1. All Ministries of the Government of India.
2. All State Governments etc
3. P.S. to Minister of Food & Agriculture, C.D. & Co-operation.
4. P.S. to Minister of State.
5. Chairman, Evaluation Committee, C/o C.C.G., New Link Road, New Delhi.
6. Secretary, Evaluation Committee for CCG New Link Road, New Delhi.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. J. MAJUMDAR, Additional Secy.

New Delhi, the 13th December 1967

No. 31-6/67-FY(P).—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 12-24/57-FY(D) dated the 1st April, 1958 and Notification No. 31-2/66-FY(P) dated the 20th October, 1966, the President is pleased to nominate Shri Edmund Fernando, M.L.A., 15, Pudupet South Street, Palayamkottai, Tirunelveli District, in place of Shri T. Muthukannappan as Non-official Member of the Central Board of Fisheries.

GODWIN ROSE, Jt. Secy.

(I.C.A.R.)

New Delhi, the 13th December 1967

No. 29(1)/66-CDN(1).—Dr. D. R. Gadgil, former Vice-Chancellor, University of Poona, who had been nominated as a representative of the University Grants Commission on the Standing Committee for Agricultural Education of the Indian Council of Agricultural Research for the period ending the 30th July, 1969, or till such time as his successor was nominated on the Committee, whichever period expires earlier, has expressed his inability to serve as a member of that Committee. Dr. D. R. Gadgil has thereby under the provisions of Rule 77 read with Rule 11 of the Rules of the Society ceased to be a member of the Committee.

Professor V. M. Dandekar, Director, Gokhale Institute of Politics and Economics, Poona, is hereby nominated as member of the Standing Committee for Agricultural Education to represent the University Grants Commission thereon, *vice*. Dr. D. R. Gadgil for the period ending the 30th July 1969, or till such time as his successor is nominated on the Committee whichever period expires earlier.

The 20th December 1967

No. 30(1)/67-CDN(1).—Under the provisions of Rule 34 read with Rules 35 and 10 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the following persons who ceased to be members of the Governing Body the Council as reconstituted under this Ministry's Resolution No. 27/66-Reorgn.(CC), dated the 17th February, 1966, with effect from the 25th October, 1967, under Rule 35 read with Rule 11(b) of those Rules, are hereby reappointed as members of the Governing Body for the unexpired portion of their term of membership of that Body, *vice*. from the 25th October, 1967 to the 16th February, 1969 or till such time as their successors are appointed on that Body, whichever period expires earlier :—

1. Dr. Vikram A. Sarabhai, Chairman Atomic Energy Commission, Bombay
2. Dr. M. D. Patel, Director Institute of Agriculture, Anand.

No. 30(1)/67-CDN(1).—Under the provisions of Rule 35 read with Rule 11(b) of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the following persons who had been appointed as members of the Governing Body of the Council,

as reconstituted under this Ministry's Resolution No. 2-7/66-Reorgn.(CC), dated the 17th February, 1966, have ceased to be members of that Body with effect from the 25th October, 1967 :—

1. Shri N. Naroatham Reddy,
Member, Rajya Sabha,
Hyderabad.
2. Shri M. Y. Ghorpade, Shivapur,
Bellary District,
Mysore.

Under the provisions of Rule 34 read with Rules 35 and 10 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the following persons are hereby appointed as members of the Governing Body of the Council for the period from the 15th December, 1967 to the 16th February, 1969, or till such time as their successors are appointed on that Body, whichever period expires earlier :—

1. Shri Shishir Kumar, Member, Rajya Sabha, Arrah, Bihar.
2. Shri Shah Nawaz Khan, "Aithal Farm", Village Aithal, (District Saharanpur), Uttar Pradesh.

P. S. HARIHARAN, Dy. Secy.

(Department of Food)

New Delhi, the 14th December 1967

No. 21(3)/67-Tech.I.—In partial modification to the Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) Notification No. 21(3)/67-Tech.I, dated the 2nd November, 1967 relating to the constitution of the Central Fruit Products Advisory Committee, the following shall be substituted in place of the existing entry, against serial number 15 :—

Dr. Y. K. Subramanyam,
Deputy Director General of Health Services,
Ministry of Health & Family Planning, Nirman Bhavan,
New Delhi.

ORDER

NOTIFICATION be published in the Gazette of India for general information.

T. R. PARMESHWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

RESOLUTION

New Delhi, the 20th November 1967

SUBJECT :—Central Advisory Board of Physical Education and Recreation: Reconstitution of....

No. F. 8-1/66-Y.S.4.—In continuation of the Ministry of Education Resolution No. F. 23-34/60-PEU dated the 19th May, 1961, as amended from time to time, on the subject cited above, the following further amendment is hereby made to the said Resolution :—

Item No. 7 under Clause 2 shall be replaced by the following :—

"Under Secretary, (Youth Services), Ministry of Education, Government of India, to serve as Member-Secretary of the Board."

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

A. B. CHANDIRAMANI, Jt. Educational Adviser

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Deptt. of Labour & Employment)

New Delhi, the 18th December 1967

No. WE.4/1/36/66.—Consequent to the amendment of clause (g)(iii) of rule 3 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, decided upon at its 10th annual meeting held at New Delhi on 7th November, 1967, the words "six months" appearing in para 1 of the Government of India, Deptt. of Labour and Employment Notifications No. WE.4/1/36/66 dated 27th October, 1967 and 28th November, 1967, shall be constituted by the words "one year".

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.